केन्द्र सरकार द्वारा 1984–85 से 1992–93 तक 1,45,96,595/- रुपए की सहायता दी गई है ।

(ख) से (घ) हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35 के तहत कुल्लू जिले में ग्रेट हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान बनाने के अपने इरादे के बारे में एक अधिसूचना जारी की है तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उक्त अधिनियम की धारा 19 की शर्तों के अनुसार कलैक्टर के रूप में उद्यान की सीमाओं के भीतर आने वाली भूमि पर लोगों के अधिकारों की जांच कर रहे हैं। प्रभावित लोगों को मुआवजे का भुगतान कलैक्टर के अंतिम निर्णय एवं अधिकारों के निर्धारण पर निर्भर करेगा।

(ङ) उन सभी व्यक्तियों, जिनके अधिकार प्रभावित हुए हैं, को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत मुआवजा दिया जायगा।

विभिन्न नदियों की सफाई हेतु योजना तैयार किया जाना

1711. श्री राम नरेश यादव : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न नदियों की सफाई हेतु कोई योजना तैयार की है ताकि इन्हें प्रदूषण-मुक्त किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या सरकार प्रदूषण को रोकने के लिये कोई कानून बनाने अथवा जल-प्रदूषण को कम से कम करने के लिये दूसरे देशों से सहयोग प्राप्त करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) देश की प्रमुख नदियों के प्रदूषण निवारण के लिये एक राष्ट्रीय नदी कार्य योजना का प्रतिपादन किया जा रहा है । इस संबंध में विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसमें अन्य देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की संभावना का पता लगाया जाना शामिल

Forest land for plantations

1712. SHRIMATI KAMLA SINHA: ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a.) whether it is a fact that paper industry has sought cheap forest land plantations;

Co) if so, to what extent the pro posal has been appreciated by Gov-nent;

(c) whether it is a fact that paper industry has been given enormous subsidy in terms of state-supplied raw material; and

(d) what steps are taken by Gov-tnent to ensure ecological standards in view of growing demands of the paper industry?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) National Fovest Policy, 1988 states that that the practice of supply of forest produce to industry at concessional price should cease.

(d) To ensure ecological standards in view of growing demands of the paper industry, steps taken by the government are as follows: —

(i) Encouraging manufacture of paper from agricultural wastes.